IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

IRP Polity (हिंदी) Final Compilation

DELHI

5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi –110005. Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

Ph:0114167500

BANGALORE

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar Service Road, Vijaynagar, Bangalore 560040. PH: 09035077800 / 7353277800

support@iasbaba.com

www.iasbaba.com

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने परिषद में कार्य संचालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर वायसराय को सशक्त बनाया।
2. भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (d)

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने परिषद में कार्य संचालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर वायसराय को सशक्त बनाया।

इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आरंभ की गई 'पोर्टफोलियो' प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था तथा उसे अपनी ओर से उनके विभाग के मामलों पर अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

इसलिए कथन 1 सही है।

भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किया गया था। इसलिए, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सांप्रदायिक पुरस्कार ने सिक्खों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल विस्तारित किया।
2. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (b)

सांप्रदायिक पुरस्कार ने न केवल मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक-पृथक निर्वाचन मंडलों को जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) तक भी विस्तारित किया।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जब भी संविधान सभा, विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, इसकी अध्यक्षता डॉ.राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गयी।
2. संविधान सभा ने डॉ.राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (b)

जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माता सभा के रूप में हुई तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की तथा जब यह विधायी निकाय के रूप में मिली, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर द्वारा की गयी थी। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंह (Lion) को संविधान सभा के प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।
2. बी.एन. राव को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (c)

हाथी (Elephant) को संविधान सभा के प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

एच.वी.आर. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
2. ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा भारतीय संघवाद को सौदेबाजी युक्त संघवाद (bargaining federalism) के रूप में वर्णित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (a)

संविधान में अनुच्छेद 394-ए के तहत, अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रदान करने का प्रावधान है।

इसलिए कथन 1 सही है।

मॉरिस जोन्स द्वारा भारतीय संघवाद को सौदेबाजी युक्त संघवाद (bargaining federalism) के रूप में वर्णित किया गया है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.6) भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रस्तावना और संविधान के एक विशिष्ट प्रावधान के बीच संघर्ष की स्थिति में उत्तरार्द्ध प्रबल होगा।
2. इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा एलआईसी ऑफ इंडिया वाद में कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (a)

प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को अधिरोहित नहीं कर सकती है। दोनों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, उत्तरार्द्ध प्रबल होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

बेरुबरी यूनियन मामले (1960) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

केशवानंद भारती मामले (1973) में, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व विचार को खारिज कर दिया तथा कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

LIC ऑफ इंडिया वाद (1995) में भी उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान की अभिन्न अंग है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं
2. दिल्ली और पुदुचेरी, केवल दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (c)

संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं

इसलिए कथन 1 गलत है।

दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.8) भारत के संघ और क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत संघ (Union of India) में केवल राज्य शामिल हैं।
2. सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।
3. आंध्र प्रदेश, भारत में भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य है।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.8) Solution (c)

भारत संघ में वे राज्य शामिल हैं जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियाँ साझा करते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

उच्चतम न्यायालय ने 1969 में निर्णय सुनाया कि, भारत और अन्य देशों के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य है

इसलिए कथन 3 सही है।

Q.9) निम्नलिखित में से कौन सा वंचन (Deprivation), भारतीय नागरिकता खोने का कारण नहीं है?

a) नागरिक ने धोखाधड़ी करके नागरिकता प्राप्त की है।
b) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है।

c) नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
d) नागरिक सात वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है।

Q.9) Solution (c)

समाप्ति के द्वारा (By Termination): जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

इसलिए कथन c गलत है।

Q.10) नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है।
2. नागरिकता से संबंधित बनाए गए किसी भी कानून को संवैधानिक संशोधन माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (b)

भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है।

इसलिए कथन 1 सही है

संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में बनाए गए कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है

Q. 11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 12 में उल्लिखित 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत LIC आता है।
2. अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते समय उच्च न्यायालय को 'राज्य' नहीं माना जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 11) Solution (d)

एलआईसी, ओएनजीसी 'राज्य' की परिभाषा के तहत आते हैं जैसा कि अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 12 के तहत, अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते समय उच्च न्यायालय को 'राज्य' नहीं माना जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 14 विदेशियों के लिए भी लागू है।
2. 'विधि के समक्ष समता' (Equality before law) यह बताता है कि बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 12) Solution (a)

अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी, सभी के लिए भी लागू है।
इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति जैसे सांविधिक निगम, कम्पनियाँ, पंजीकृत समितियां आदि भी सम्मिलित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

'विधियों के समान संरक्षण' (Equal protection of laws) का अर्थ है कि बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 13) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 15 (2) राज्य और निजी व्यक्तियों, दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है।

2. संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सूचित करने वाले संकेतकों में से एक के रूप में पारिवारिक आय (family income) का उल्लेख है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 13) Solution (c)

अनुच्छेद 15 (2) राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक पिछड़ेपन के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।
2. अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार, निगमों जैसे विधिक व्यक्तियों (legal persons) के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 14) Solution (d)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है तथा यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस अधिकार का उल्लंघन न हो।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल राज्य कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षित हैं तथा न कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। इसके अलावा, ये अधिकार केवल नागरिकों और एक कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन विदेशी या विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनियों या निगमों, आदि के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
2. भारतीय संविधान में 'निवारक निरोध' का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 15) Solution (a)

भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने का अधिकार, 1) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा, 2) आम जनहित में, के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने संविधान के अभिन्न अंग के रूप में निवारक निरोध प्रावधान नहीं अपनाया है जैसा कि भारत में किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अज्ञात है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 16) भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये भारत के सभी निवासियों पर उनकी जाति, पंथ, लिंग और धर्म के बावजूद लागू हैं।
2. संसद मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी दंड का आरोपण नहीं कर सकती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 16) Solution (c)

मौलिक अधिकारों में से कुछ के विपरीत जो सभी व्यक्तियों के लिए विस्तारित होते हैं चाहे नागरिक हों या विदेशी, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं तथा विदेशियों तक विस्तारित नहीं हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, संसद उन्हें उपयुक्त कानून द्वारा लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 17) 'आर्थिक न्याय', भारतीय संविधान के उद्देश्य को कहाँ सम्मिलित किया गया है

a) प्रस्तावना और मौलिक अधिकार
b) प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
c) मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
d) प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत।

Q. 17) Solution (b)

प्रस्तावना:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP):

अनुच्छेद 38: न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना- तथा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना।

Q. 18) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 'अद्वितीय विशेषता' है?

1. प्रस्तावना
2. मौलिक अधिकार
3. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
4. मौलिक कर्तव्य

दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 2
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3 और 4

d) केवल 3

Q. 18) Solution (d)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक 'अद्वितीय विशेषता' है।

Q. 19) निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या योजना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है?

1. गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPBBDD)
2. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
3. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
4. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 2
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q. 19) Solution (d)

- आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए (अनुच्छेद 48) - गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPBBDD)
- समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए (अनुच्छेद 39 ए) - कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना (अनुच्छेद 42) - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना; (अनुच्छेद 39) - पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

Q.20) मिनर्वा मिल्स केस (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक क्रांति (social revolution) के लिए प्रतिबद्धता का मूल नहीं है।

1. मौलिक अधिकार
2. मौलिक कर्तव्य
3. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q. 20) Solution (b)

मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल आधार हैं।

Q. 21) **निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
2. राज्य धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 21) Solution (a)

अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 25 (2) के अनुसार, राज्य धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य कोष से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा।
2. राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि जब यह धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता वाले किसी भी ट्रस्ट के तहत स्थापित हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 22) Solution (d)

राज्य कोष से पूर्णत: बनाए गए किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा।

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य कोष से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उस संस्था में किसी भी धार्मिक निर्देश या पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 28 के तहत, राज्य कोष से पूर्णत: बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान राज्य द्वारा प्रशासित उन शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, जो किसी भी विन्यास या ट्रस्ट के तहत स्थापित किए गए हैं, इस तरह के संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति होगी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी भी नागरिक को निवास स्थान के आधार पर राज्य निधियों से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
2. सार्वजानिक हित में दो या दो से अधिक निगमों के समामेलन के लिए प्रदान किया गया कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 23) Solution (b)

किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधियों से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सार्वजनिक हित में दो या अधिक निगमों के समामेलन के लिए प्रदान किया गया कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 31 A में 9 वीं अनुसूची के बारे में उल्लेख है।
2. अनुच्छेद 39 (c) को प्रभावी करने वाला कोई कानून अनुच्छेद 19 के साथ उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 24) Solution (a)

अनुच्छेद 31 B में 9 वीं अनुसूची के बारे में उल्लेख है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 39 (b) या 39 (c) को प्रभावी करने वाला कोई कानून अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के साथ उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 32 संविधान की मूल अवसंरचना (basic structure) का एक हिस्सा है।

2. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल (original) और अनन्य (exclusive) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 25) Solution (a)

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 32 संविधान की मूल अवसंरचना का एक हिस्सा है।

इसलिए कथन 1 सही है।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 26) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSPs) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इन सिद्धांतों की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलियाई संविधान में हुई है।
2. वे देश के शासन में मौलिक (fundamental) हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 26) Solution (b)

संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे मूलतः स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

स्वयं संविधान (अनुच्छेद 37) कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं तथा कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 27) निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?

a) बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित अवसर
b) ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित रखना।
c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना।
d) आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना।

Q. 27) Solution (c)

- अनुच्छेद 39- बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित अवसर
- अनुच्छेद 48 - आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना
- अनुच्छेद 49- ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना, अनुच्छेद 51 ए (सी) के तहत मौलिक कर्तव्य है।

Q. 28) सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है।
2. सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है।
3. जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभावित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1 और 2

Q. 28) Solution (a)

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (**writ jurisdiction**) सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, न कि अन्य उद्देश्यों के लिए।

इसलिए कथन 2 गलत है।

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) अनन्य नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ समवर्ती है। इसका अर्थ है कि, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 29) निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी?

a) न्यायमूर्ति शाह समिति
b) न्यायमूर्ति वर्मा समिति
c) स्वर्ण सिंह समिति
d) फजल अली समिति

Q. 29) Solution (c)

- 1976 में, कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की।
- न्यायमूर्ति शाह समिति का गठन आंतरिक आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग को देखने के लिए किया गया था।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति को कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व के बारे में देखने के लिए गठित किया गया था।
- राज्य पुनर्गठन आयोग में फ़ज़ल अली, के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरु शामिल थे। इसकी कुछ सिफारिशों को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया था

Q.30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वैज्ञानिक स्वभाव तथा जांच और सुधार की भावना को विकसित करना।
2. लोगों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
3. देश की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना तथा संरक्षित करना।
4. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना।

उपरोक्त में से कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है?

a) 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 3 और 4
d) केवल 2

Q. 30) Solution (c)

मौलिक कर्तव्य (51A):

यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा-

- वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जांच और सुधार की भावना को विकसित करना;
- हमारी सामासिक संस्कृति एवं मूल्यों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना;
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना;

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP)

- लोगों के जीवन स्तर और पोषण के स्तर को बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना (अनुच्छेद 47)।

Q. 31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
2. राष्ट्रपति संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक वापस नहीं कर सकता है, लेकिन सहमति देने से मना कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 31) Solution (b)

संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी होती है। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है और न ही संसद में पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
2. छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 32) Solution (b)

राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत) द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. बुनियादी ढांचे का सिद्धांत 1971 के बाद किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
2. व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा संविधान के बुनियादी ढांचे के तत्वों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 33) Solution (b)

वामन राव मामले (1981) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुनियादी ढांचे' के सिद्धांत को निर्गत किया और आगे स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल, 1973 (अर्थात, केशवानंद भारती वाद में दिए गए निर्णय की तारीख के बाद किए गए संविधान संशोधन पर लागू होगा)।

इसलिए कथन 1 गलत है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, कल्याणकारी राज्य, कानून का नियम, समता के प्रधानता आदि संविधान के बुनियादी ढांचे के कुछ तत्व हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति को उस कार्यालय में दोबारा नहीं चुना जाएगा।
2. यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो इस तरह की घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कृत्यों को अमान्य नहीं किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 34) Solution (a)

अनुच्छेद 56: एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिसने धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है, तथा उस कार्यालय के पुन: चुनाव के लिए पात्र होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है
2. राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही केवल लोकसभा में आरंभ की जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 35) Solution (d)

प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में अपनी शपथ लेता है तथा उसकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में लेता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 36) संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. ऐसे विधेयक के पारित होते समय गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 36) Solution (a)

विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

प्रत्येक सदन को पृथक रूप से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में, विधेयक के विचार-विमर्श और पारित होने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 37) एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) द्वारा निम्नलिखित में से किसे चुना जाता है?

1. विधान सभा के सदस्य
2. उप-राष्ट्रपति
3. राज्यसभा के सदस्य

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 2
b) 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 37) Solution (c)

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, अर्थात् एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। भारत में, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत सभी दलों के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। यहां तक कि संख्या के सबसे छोटे हिस्से को विधायिका में प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा मिलता है।
- संविधान ने लोकसभा के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (territorial representation) की प्रणाली को अपनाया है।

Q. 38) राष्ट्रपति को 'संविधान के उल्लंघन' (violation of the Constitution) के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. संविधान शब्द 'संविधान के उल्लंघन' के अर्थ को परिभाषित नहीं करता है।
2. संविधान राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है तथा संसद को कानून बनाने के लिए छोड़ दिया है।
3. संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 3

Q. 38) Solution (a)

राष्ट्रपति को 'संविधान के उल्लंघन' के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालाँकि, संविधान 'संविधान के उल्लंघन' वाक्यांश का अर्थ परिभाषित नहीं करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

चूंकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया और आधार प्रदान करता है, इसलिए अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुसार, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता।

इसलिए कथन 2 गलत है।

संसद के किसी भी सदन के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं;

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q. 39) राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास मृत्युदंड के संबंध में निलंबन, लघुकरण और रूपांतरण की समवर्ती शक्तियां हैं।
2. राष्ट्रपति के फैसलों की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए संविधान किसी भी तंत्र को प्रदान नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 39) Solution (c)

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है; यह एक कार्यकारी शक्ति है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास मृत्युदंड के संबंध में निलंबन, लघुकरण और रूपांतरण की समवर्ती शक्तियां हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

दया के क्षेत्राधिकार के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णयों की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए संविधान किसी भी तंत्र को प्रदान नहीं करता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.40) भारत के उप-राष्ट्रपति के पद के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है / हैं?

a) इस पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए
b) इस पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य दोनों होते हैं।
c) राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में, वह उसके कार्यालय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद संभाल सकता है।
d) इस पद का प्रभारी राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है

Q. 40) Solution (c)

इस पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए

इसलिए कथन a सही है।

इस पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य दोनों होते हैं तथा निर्वाचित व्यक्ति पाँच साल की अवधि के लिए पद पर बना रहता है।

इसलिए कथन b सही है।

राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में, वह उसके कार्यालय को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए संभाल सकता है।

इसलिए कथन c गलत है।

इस पद का प्रभारी राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है

इसलिए कथन d सही है।

Q. 41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यदि राष्ट्रपति का कार्यालय मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है, तो नव निर्वाचित राष्ट्रपति पूरे पांच वर्ष के लिए पद पर बने रहेंगे।
2. जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त सभी शक्तियों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 41) Solution (d)

यदि राष्ट्रपति का पद इस्तीफा, मृत्यु, या हटाए जाने से रिक्त हो जाता है, तो नव निर्वाचित राष्ट्रपति पूरे पांच वर्ष तक पद पर बने रहते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

जब कोई भी व्यक्ति, अर्थात, उप-राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हों, तो वे राष्ट्रपति को प्राप्त सभी शक्तियों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेते हैं तथा ऐसे भत्ते, परिलब्धियों और विशेषाधिकार हकदार होते हैं जैसे कि संसद द्वारा निर्धारित किए गए हों।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 42) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय रिक्त होने पर राष्ट्रपति इनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं।
2. सभापति और उप-सभापति दोनों के पद रिक्त होने पर, उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 42) Solution (a)

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय रिक्त होने पर राष्ट्रपति इनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति इनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए राज्य सभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है, तो वह पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस नहीं कर सकता है।
2. पूर्ण/ निरपेक्ष वीटो (Absolute Veto) का इस्तेमाल कभी भी किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 43) Solution (d)

जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है, तो वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। (धन विधेयक को छोड़कर)

इसलिए कथन 1 गलत है।

पूर्ण/ निरपेक्ष वीटो का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया है। 1954 में, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति रोक ली थी। PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था। लेकिन, जब राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया गया।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद के केवल एक सदन के सत्र में होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
2. भारत में राष्ट्रपति की अध्यादेश-प्रवर्तन शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 44) Solution (b)

अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो क्योंकि एक कानून दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तथा केवल एक सदन द्वारा नहीं।

इसलिए कथन 1 सही है।

भारत में राष्ट्रपति की अध्यादेश-प्रवर्तन शक्ति असामान्य है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान में नहीं पाई जाती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 45) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य होते हैं।
2. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 45) Solution (a)

उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

उन्हें राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है तथा लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रस्ताव को राज्यसभा में एक प्रभावी बहुमत (effective majority) से और लोकसभा में एक साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

इसलिए कथन 2 गलत है।

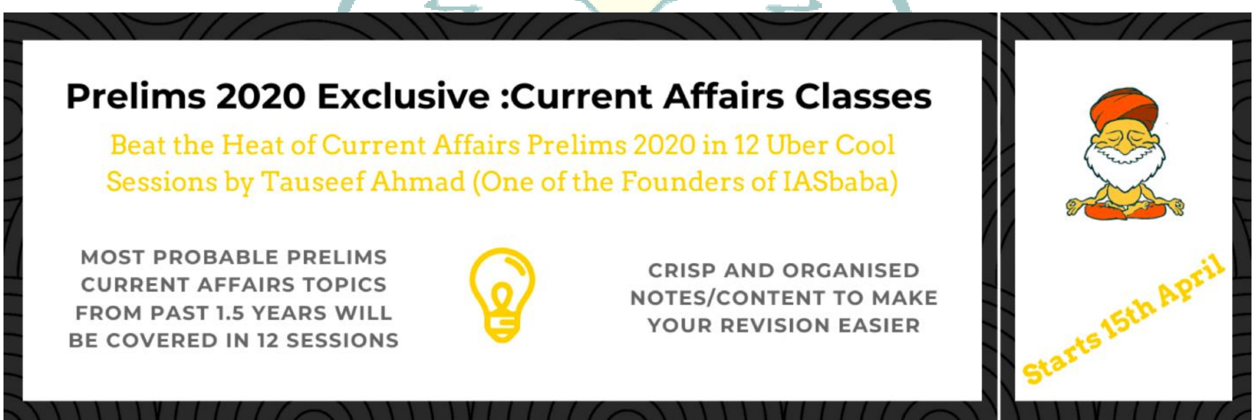

Q. 46) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं है
2. एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 46) Solution (b)

संविधान में प्रधान मंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।

इसलिए कथन 1 सही है।

1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा; अन्यथा, वह प्रधान मंत्री पद खो देगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 47) प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री राय के अंतर के मामले में एक मंत्री को इस्तीफा देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।
2. एक पदधारी प्रधानमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु छह महीने के भीतर मंत्रियों की परिषद को भंग कर देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 47) Solution (a)

प्रधानमंत्री राय के अंतर के मामले में एक मंत्री को इस्तीफा देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

एक प्रधान मंत्री का इस्तीफा या मृत्यु स्वचालित रूप से तत्काल मंत्रियों की परिषद को भंग कर देती है तथा इस तरह एक शून्य उत्पन्न करती है।

इसलिए कथन 2 गलत है

Q. 48) भारत के महान्यायवादी (देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महान्यायवादी का कार्यालय संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है।

2. उनके पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।
3. संविधान में उसके निष्कासन की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1 और 2

Q. 48) Solution (a)

संविधान (अनुच्छेद 76) ने भारत के लिए महान्यायवादी के कार्यालय के लिए प्रावधान प्रदान किया है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

महान्यायवादी के कार्यालय का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।

इसलिए कथन 2 सही है।

संविधान में उसके निष्कासन की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 49) निम्नलिखित में से कौन संसदीय विशेषाधिकार के हकदार हैं?

1. महान्यायवादी
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
3. केंद्रीय मंत्री
4. राष्ट्रपति
5. राज्य के महाधिवक्ता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) 1, 2 और 4
b) 1, 3, 4 और 5
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1, 3 और 5

Q. 49) Solution (d)

- संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट हैं। संविधान ने राज्य विधायिका को भी विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।
- इनमें महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं।

Q.50) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
2. मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्ति का कोई भी अभ्यास असंवैधानिक माना जाता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 50) Solution (a)

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व के अधीन हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। बिना सहायता और सलाह के कार्यकारी शक्ति का कोई भी अभ्यास अनुच्छेद 74 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 51) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार, संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होंगे।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 51) Solution (d)

अनुच्छेद 79:

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोक सभा होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। यहाँ कार्यकारी और विधायिका का कठोर पृथक्करण देखा जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 52) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
2. राज्यसभा के सेवानिवृत्त मनोनीत सदस्य अधिकतम तीन बार पुन: नामांकन के लिए पात्र होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 52) Solution (d)

संविधान कहता है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस तरह से चुना जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा वर्णित करती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुन: चुनाव और नामांकन के लिए पात्र होते हैं। इसपर कोई प्रतिबंध नहीं है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 53) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल छह वर्ष निर्धारित किया जाता है।
2. अधिकृत होने के बावजूद, संसद ने संसद की सदस्यता के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 53) Solution (d)

संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है तथा इसे संसद पर छोड़ दिया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद की सदस्यता के लिए संवैधानिक योग्यता के अलावा संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) में कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ सम्मिलित की हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 54) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान () कर सकते हैं।
2. राज्य सभा के सभापति के पास मत डालने का अधिकार होता है (बराबर के मामले में, जब उप-राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 54) Solution (b)

भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान (prorogue) कर सकते हैं, लेकिन केवल लोकसभा को भंग (dissolve) कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

सभापति को बोलने का अधिकार होगा, और अन्यथा, जब उप-राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से हटाने का कोई भी प्रस्ताव परिषद में विचाराधीन हो, राज्य सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन यह अनुच्छेद 100 से संबंधित नहीं होगा तथा इस तरह की कार्यवाही के दौरान इस तरह के संकल्प या किसी अन्य मामले पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 55) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान संसद के दोनों सदनों के लिए समान (common) पदों (सचिवीय कर्मचारियों) के सृजन के लिए एक कठोर रोकथाम हेतु प्रावधान प्रदान करता है।
2. सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 55) Solution (b)

अनुच्छेद 98 (1)

संसद के प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवीय स्टाफ होगा:
बशर्ते कि संसद के दोनों सदनों में समान पदों के सृजन को रोकने के रूप में इस खंड में कुछ भी नहीं कहा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 100 (1)

संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेगा।

अध्यक्ष या सभापति, या इस तरह के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होंगे, जो पहली बार में मत नहीं डालेंगे, लेकिन मतों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत डालेंगे।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 56) सदन के कार्य संचालन के स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, आवश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो
2. यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।

3. इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 56) Solution (d)

स्थगन प्रस्ताव संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है

यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, जरूरी और सार्वजनिक महत्व का हो

इसलिए कथन 1 सही है।

यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

इसे किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 57) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयक पर लागू होती है।
2. राज्यसभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 57) Solution (c)

संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होती है, न कि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, तो राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्य सभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 58) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारित व्यय (charged expenditure) संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य होता है
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आती है।
3. ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 58) Solution (d)

भारित व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है, इसपर केवल संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की केवल पेंशन भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

ऋण, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के भारित व्यय की श्रेणी में आता है।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 59) निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खाते (Public Account) में जमा किया जाता है?

1. भविष्य निधि जमा
2. ट्रेजरी बिल जारी करके संग्रहित ऋण

3. प्रेषण (Remittances)
4. बचत बैंक जमा

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1, 3 और 4
c) केवल 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q. 59) Solution (b)

भारत का सार्वजनिक खाता: भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन (भारत के समेकित निधि में जमा किए गए धन के अतिरिक्त) को भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा।

इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण शामिल होते हैं।

Q.60) भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।
2. इस निधि में समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि को जमा किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 60) Solution (d)

इस निधि को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तथा वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान ने 'भारत की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया है, जिसमें कानून द्वारा निर्धारित राशियों को समय-समय पर जमा किया जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 61) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सदन के नियमों में 'सचेतक' (whip) के कार्यालय का उल्लेख किया गया है।
2. 'विपक्ष के नेता' का कार्यालय संसदीय क़ानून में उल्लिखित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 61) Solution (a)

'सचेतक' (whip) का कार्यालय न तो भारत के संविधान में और न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय क़ानून में उल्लिखित है। यह संसदीय सरकार के कन्वेंशनों पर आधारित है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सदन के नेता और विपक्ष के नेता के कार्यालयों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, उनका उल्लेख क्रमशः सदन के नियमों और संसदीय क़ानून में किया गया है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 62) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. स्थगन (adjournment) की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है जबकि अनिश्चित कालीन स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है
2. किसी सदन के सत्रावसान और इसके नए सत्र के पुनर्गठन के बीच के काल को अवकाश (recess) कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 62) Solution (b)

स्थगन के साथ-साथ अनिश्चित कालीन स्थगन (adjournment sine die) की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

किसी सदन के सत्रावसान और इसके नए सत्र के पुनर्गठन के बीच के काल को अवकाश (recess) कहा जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 63) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक बार सत्र का व्यवसाय पूरा हो जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है।
2. सभी लंबित बिल, लोक सभा के सत्रावसान पर समाप्त (lapse) हो जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 63) Solution (b)

एक बार सत्र का व्यवसाय पूरा हो जाने के बाद, राष्ट्रपति सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सत्रावसान बिल या सदन के समक्ष लंबित किसी अन्य व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, सभी लंबित नोटिस सत्रावसान पर समाप्त हो जाते हैं और अगले सत्र में फिर से नोटिस जारी की जाती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 64) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोरम (Quorum) लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का दसवां (one-tenth) हिस्सा है, जबकि राज्यसभा के लिए यह पन्द्रहवां (one-fifteenth) है।
2. कोरम की गणना, पीठासीन अधिकारी को छोड़कर की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 64) Solution (c)

कोरम पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होता है।

इसलिए कथन 1 और 2 गलत हैं।

Q. 65) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद में अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है।
2. संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 65) Solution (c)

संसद में अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है तथा इसलिए पूरक प्रश्नों को पूछा जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 66) निम्नलिखित में से कौन संसदीय विशेषाधिकार के हकदार हैं?

1. महान्यायवादी
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
3. राष्ट्रपति
4. उप-राष्ट्रपति
5. केंद्रीय मंत्री

सही कूट का चयन करें:

a) केवल 1, 3 और 5
b) केवल 1,2,3 और 5
c) केवल 1 और 5
d) 1, 2,3,4 और 5

Q. 66) Solution (c)

संविधान ने राज्य विधायिका (या संसद) के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित किया है, जिन्हें राज्य विधायिका या उसकी किसी समिति की सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। इनमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री (केंद्रीय मंत्री) शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल (राष्ट्रपति) तक विस्तारित नहीं हैं, जो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है।

Q. 67) 'अतिरिक्त अनुदान' (Excess grant) को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?

a) व्यापार सलाहकार समिति
b) आकलन समिति
c) लोक लेखा समिति
d) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

Q. 67) Solution (c)

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए अनुमोदित राशि से अधिक धन खर्च किया गया हो तो अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इसपर वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है।

मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

Q. 68) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही विनियोग अधिनियम बनता है।
2. सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की आकस्मिकता निधि से धन नहीं निकाल सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 68) Solution (a)

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है।

संविधान कहता है कि 'कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत के समेकित कोष से कोई धन नहीं निकाला जाएगा'।

Q. 69) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों (Consultative committees) का गठन किया जाता है।
2. परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 69) Solution (c)

संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। परामर्शदात्री समितियाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबद्ध होती हैं

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.70) संसदीय फोरमों (Parliamentary Forums) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय फोरमों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
2. संसदीय फोरमों में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 70) Solution (c)

लोक सभा अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसमें राज्य सभा के सभापति पदेन अध्यक्ष होता है, संसदीय फोरम को छोड़कर सभी फोरमों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

प्रत्येक संसदीय फोरम में 31 से अधिक सदस्य (राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति को छोड़कर) शामिल होते हैं, जिनमें से अधिकतम 21 लोकसभा से होते हैं और अधिकतम 10 राज्यसभा से होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 71) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करती है।
2. संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए तभी योग्य माना जाता है, जब वह राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 71) Solution (c)

भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडाई मॉडल पर आधारित है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान में केवल दो योग्यताएँ हैं:

कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 72) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यपाल को पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
2. संविधान कोई आधार वर्णित नहीं करता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 72) Solution (b)

राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में, उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान कोई आधार वर्णित नहीं करता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 73) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य के महाधिवक्ता को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जैसा राज्यपाल निर्धारित कर सकता है।
2. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 73) Solution (a)

राज्यपाल एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। राजयपाल के प्रसादपर्यंत महाधिवक्ता पद पर बना रहता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 74) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति (discretionary power) है।
2. राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, यदि ऐसा मृत्युदंड राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 74) Solution (c)

राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है या वापस ले सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि किसी राज्य कानून के आधार पर मृत्युदंड दिया जाता है, तब भी क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 75) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुसार आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे विधान सभा में बहुमत साबित करना होगा।
2. उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र पदनाम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 75) Solution (d)

संविधान के अनुसार आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे विधान सभा में बहुमत साबित करना होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति एक व्यवस्थापक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है; यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। वर्तमान में, यह दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मामले में उपराज्यपाल है तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के मामले में प्रशासक है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 76) निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है?

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. तेलंगाना
4. ओडिशा
5. कर्नाटक

सही कूट का चयन करें:

a) केवल 1, 3 और 5
b) केवल 1, 2, 3 और 5
c) केवल 1 और 5
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q. 76) Solution (b)

भारत में छह राज्यों में विधान परिषदें हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

Q. 77) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीन सूचियों (केंद्र, राज्य, समवर्ती) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
2. संसद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 77) Solution (a)

केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसद तीन सूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

Q. 78) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है जो एक राज्यपाल की तरह राज्य के प्रमुख के समान होता है।
2. राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आसन्न केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 78) Solution (b)

प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है तथा राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 79) भारतीय संदर्भ में, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional discretion) है?

1. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश
2. एक आसन्न केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
3. राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक का आरक्षण (Reservation)।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 79) Solution (d)

राज्यपाल के पास निम्नलिखित मामलों में संवैधानिक विवेकाधिकार है:

1. राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक का आरक्षण।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
3. आसन्न केंद्रशासित प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
4. एक स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद को खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा देय राशि का निर्धारण करना।
5. राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना।

Q.80) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद द्वारा विधान परिषदों का निर्माण अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
2. विधान परिषदों के निर्माण के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 80) Solution (b)

संसद एक विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या इसका सृजन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है।

इस तरह के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात् विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत तथा विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत।

संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान के संशोधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए तथा इसे कानून के एक साधारण भाग की तरह पारित किया जाता है (अर्थात, साधारण बहुमत द्वारा)।

इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है।

Q. 81) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
2. संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी मामले में चालीस से कम नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 81) Solution (d)

प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी मामले में चालीस से कम नहीं होगी।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 82) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक वह पैंतीस साल का नहीं हो जाता।
2. संविधान किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 82) Solution (d)

कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक वह तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 83) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. विधान सभा के अध्यक्ष, विधान सभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं।
2. विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 83) Solution (a)

विधान सभा के अध्यक्ष विधान सभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 188:

विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी सदस्यता लेगा, तथा तीसरी अनुसूची के तहत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण या पुष्टि करेगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 84) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य विधान परिषद की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है।
2. यदि किसी भी समय राज्य विधान सभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन का सत्रावसान (prorogues) कर देते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 84) Solution (c)

किसी राज्य के विधानमंडल/ परिषद की बैठक का गठन करने के लिए न्यूनतम कोरम आवश्यक है, जो सदन के कुल सदस्यों का दसवां भाग होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि किसी भी समय राज्य विधान सभा की बैठक के दौरान कोई कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन को स्थगित (adjourn) कर देते हैं या बैठक को रोक (suspend) देते हैं जब तक कि कोरम पूर्ण न हो।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 85) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुना जाता है, (राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट निश्चित अवधि की समाप्ति पर), तो उसके गृह राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के विधानसभाओं में व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी। ।
2. अध्यक्ष राज्य विधान सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को अवश्य स्वीकार करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 85) Solution (d)

अनुच्छेद 190 (2): कोई भी व्यक्ति पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होगा तथा यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधानसभाओं का सदस्य चुना जाता है, तो इस तरह राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट निश्चित अवधि की समाप्ति पर, ऐसे में सभी राज्यों के विधानसभाओं में उस व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी, जब तक उसने एक विधानसभा में अपनी सीट को छोड़कर अन्य सभी से इस्तीफा नहीं दिया हो।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राज्य विधान सभा के सदस्य के किसी भी इस्तीफे के मामले में, यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा या ऐसी पूछताछ करने के बाद, जैसा कि वह उचित समझता है, अध्यक्ष या चेयरमैन, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि ऐसा इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, वह इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 86) राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a) जब एक विधेयक, जो परिषद में उत्पन्न हुआ है और विधानसभा में भेजा गया था, विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है और मृत हो जाता है।
b) विधेयक को किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
c) संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान करता है ताकि दोनों सदनों के बीच असहमति का समाधान हो सके।
d) विधान सभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन विधान परिषद ऐसा नहीं कर सकती है।

Q. 86) Solution (c)

संविधान, दोनों सदनों के बीच एक विधेयक पर असहमति के समाधान के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए तंत्र का प्रावधान प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर, साधारण विधेयक पर दोनों के बीच असहमति को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।

Q. 87) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
2. जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक रखता है, तो विधेयक की स्वीकृति में राज्यपाल की आगे कोई भूमिका नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 87) Solution (b)

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न विधान परिषद के मामले में, चेयरमैन तथा विधानसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक रखता है:

यदि विधेयक सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है और फिर से पारित हो जाता है, तो विधेयक को पुनः केवल राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है, तो यह एक अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 88) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएं।
2. किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य, कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 88) Solution (b)

विधान सभा और राज्य के विधान परिषद के सदस्य कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।

Q. 89) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक धन विधेयक राज्य विधायिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. जब राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक (राज्यपाल द्वारा) आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकते।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 89) Solution (d)

धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस नहीं कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.90) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान (prorogation) के कारण समाप्त (lapse) नहीं होगा।
2. राज्य विधान परिषद में लंबित एक विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त (lapse) नहीं होगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 90) Solution (d)

राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्य विधान परिषद में लंबित एक विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 91) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद के पास, जब आपातकाल की उद्घोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।
2. राष्ट्रपति, संसद की सहमति से, किसी भी मामले के संबंध में एक राज्य सरकार को कुछ कार्य सौंप सकता है, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 91) Solution (b)

संसद के पास, जब आपातकाल की उदघोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से किसी भी विषय के संबंध में सरकार या उसके अधिकारियों को सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकते हैं, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 92) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी केंद्रशासित प्रदेश (राज्य शामिल नहीं हैं) के मामले में, संसद के पास राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है।
2. संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 92) Solution (c)

संसद के पास भारत के केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, इस बात के बावजूद कि इस मामले को राज्य सूची में शामिल किया गया है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है। (संसद के पास अवशिष्ट कर लगाने की विशेष शक्तियां हैं)

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 93) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित न्यायिक कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र की सरकार (भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना) के साथ समझौता कर सकती है।
2. मिजोरम के राज्यपाल भी निर्देश जारी कर कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य के एक आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 93) Solution (a)

भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित किसी भी कार्यकारी, विधायी या न्यायिक कार्यों को करने के लिए भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होने के साथ किसी भी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। लेकिन ऐसा समझौता लागू होते समय किसी कानून के अधीन प्रशासित होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

असम के राज्यपाल निर्देश जारी कर यह कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिले) पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 94) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करने की शक्ति है।
2. संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 94) Solution (a)

संसद कानून द्वारा संघ सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में संसद या किसी भी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए कानून प्रदान कर सकती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 95) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर अमान्य माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।
2. केवल संसद वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बना सकती है, जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 95) Solution (b)

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहां माल, या सेवाओं की आपूर्ति, या दोनों अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 96) संविधान की 5 वीं अनुसूची के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यपाल को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (scheduled area) घोषित करने का अधिकार है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है।
3. जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श के बाद राज्यपाल को एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 96) Solution (c)

किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसकी सीमा रेखा को परिवर्तित कर सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के बारे में सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। वह जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम भी बना सकते हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 97) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल (prevails) होता है।
2. शिक्षा आरंभ में राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय थी, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय सूची में लाया गया।
3. एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 3
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 97) Solution (c)

समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल होता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

42 वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया।

इसलिए कथन 2 गलत है।

एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q. 98) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, प्रत्येक राज्य को नहीं।
2. अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान नीति आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दिया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 98) Solution (a)

सांविधिक अनुदान (Statutory Grants): अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, प्रत्येक राज्य को नहीं। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय की जा सकती है। ये राशि हर साल भारत के समेकित कोष पर भारित होती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत सांविधिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 99) केंद्र को निम्नलिखित में से किस मामले में अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है?

1. राज्य द्वारा संचार के साधनों का निर्माण और रखरखाव।
2. राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय।
3. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 99) Solution (d)

राज्य द्वारा संचार के साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के) का निर्माण और रखरखाव;

राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय;

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

Q.100) निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं (Federal features) माना जाता है?

1. लिखित संविधान
2. एकीकृत न्यायपालिका
3. शक्तियों का विभाजन
4. एकल संविधान
5. एकीकृत चुनावी मशीनरी

सही कूट का चयन करें:

a) केवल 1, 2, 4 और 5

b) केवल 1, 2, 3 और 5
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.100) Solution (c)

दोहरी राजव्यवस्था (Dual Polity), लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की कुछ संघीय विशेषताएं हैं।

एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, एकीकृत चुनाव मशीनरी, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की कुछ एकल/केंद्रीय विशेषताएं हैं।

Q. 101) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तीस होगी।
2. चौथे न्यायाधीशों के मामले (Fourth Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 101) Solution (c)

भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तैतीस (33) होगी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

तीसरे न्यायाधीशों के मामले (Third Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निर्णय सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोलेजियम से परामर्श करना चाहिए जिसमें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। (दूसरे न्यायाधीशों के मामले (second judges case) में यह केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीश था)

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 102) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 84 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 102) Solution (d)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया पर संविधान मौन है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करना एक कन्वेंशन है जिसे 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण कर सकता है जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 103) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, भारत के भीतर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, वह किसी भी न्यायालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा।
2. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 103) Solution (d)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में पदभार ग्रहण नहीं करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन किसी अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति न्यायालय में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 104) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करता है।
2. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 104) Solution (a)

जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकता है

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 105) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान यह कहता है कि कानून द्वारा संसद (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ) अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त कर सकती है।

2. भारतीय क्षेत्र में, आपराधिक मामलों के केस में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन सिविल मामलों में नहीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 105) Solution (d)

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ समय-समय पर नियुक्ति कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारतीय क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, चाहे वह एक नागरिक, अपराधी या अन्य कार्यवाही में हो, के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 106) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं की जाती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति (overriding power) के अधीन हो जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 106) Solution (c)

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति के अधीन हो जाती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण निलंबित होता है, हालांकि राज्य विधानसभाएं निलंबित नहीं होती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 107) अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a) अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
b) अनुच्छेद 358 आपातकाल घोषित होते ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है।
c) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल समाप्ति के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
d) अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है

Q. 107) Solution (b)

अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358 स्वचालित रूप से अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं करता है। यह केवल राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

आपातकाल के समाप्त होने के बाद भी, आपातकाल के दौरान की गयी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

इसलिए कथन 3 सही है।

अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में संचालित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है।

इसलिए कथन 4 सही है।

Q. 108) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 108) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

Q. 109) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) में ही रिट जारी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य (exclusive) नहीं है लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती (concurrent) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 109) Solution (c)

उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर, बल्कि अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती है। इसका अर्थ है कि, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.110) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष पर भारित किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 110) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में वर्णित उस तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन नहीं रहते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर भारित किया गया है। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 111) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संघीय न्यायालय (Federal Court) शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है।
2. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के पास सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) देने का विवेकाधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.111) Solution (b)

अनुच्छेद 135 में संघीय न्यायालय (Federal Court) शब्द का उल्लेख है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 136 (1): उच्चतम न्यायालय, अपने विवेकाधिकार से, किसी भी कारण या मामले को पारित करने या भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय, डिक्री, दृढ़ संकल्प, वाक्य या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) दे सकता है।
खंड (1) में कुछ भी सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या लागू किए गए किसी भी निर्णय पर लागू नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 112) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय दोनों उच्च न्यायालयों की पूर्व सहमति के साथ ही किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 112) Solution (b)

सर्वोच्च न्यायालय, यदि न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 113) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 143 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई राय उनके लिए बाध्यकारी है।
2. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से आम तौर पर न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 113) Solution (b)

अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है, न्यायिक घोषणा नहीं। इसलिए, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, आमतौर पर न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 114) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तीन होगी।

2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 114) Solution (a)

न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होंगी, जो किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है, जिसमें कानून का एक बड़ा प्रश्न होता है, जो इस संविधान की व्याख्या के अनुसार है या अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य के लिए है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों या कुछ अन्य न्यायाधीशों या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायालय के अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 115) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है।
2. यदि कोई प्रश्न किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित आता है, तो यह प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 115) Solution (a)

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख-न्यायालय (court of record) होगा और इस तरह के न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

यदि कोई प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न का निर्णय लिया जाएगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 116) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोई भी व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला हो, वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं करेगा।
2. जब एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों को न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 116) Solution (d)

कोई भी व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद, एक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में या भारत में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर, कार्यालय के कर्तव्यों को ऐसे किसी एक के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। राष्ट्रपति न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 117) संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं।

2. केंद्र यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 117) Solution (a)

वित्तीय आपातकाल के मामले में, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

केंद्र यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित होंगे।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 118) राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल संचलन में रहता है, राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यदि संसद सत्र में नहीं होती है।
2. राष्ट्रपति या तो केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं और राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 118) Solution (d)

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संचलन में हो, राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यदि संसद सत्र में नहीं हो।

इसलिए कथन 1 सही है।

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संचलन में हो, राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 119) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि उच्च न्यायालय के कार्य (business) में अस्थायी वृद्धि होती है, तो राष्ट्रपति एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
2. उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 119) Solution (c)

यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य (business) में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसके कार्य के शेष बचे रहने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या उस समय बढ़नी चाहिए, तो विधिवत योग्य व्यक्ति को इस अवधि के लिए न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है, इसकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q.120) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) है जबकि विवाह, तलाक से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
2. सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है तथा निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 120) Solution (b)

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों में है, जबकि उच्च न्यायालय का विवाह, तलाक, वसीयत, संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद आदि मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है तथा निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 121) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग X को जोड़ा गया है।
2. 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 121) Solution (b)

73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग XI को जोड़ा गया है।

अतः कथन 1 गलत है।

73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा है।

अतः कथन 2 सही है।

Q. 122) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। हालाँकि, इन एक तिहाई सीटों की गणना अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर की जाती है।
2. ग्राम स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 122) Solution (d)

प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें (इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट शामिल है) महिलाओं के लिए आरक्षित होती है।

अतः कथन 1 गलत है।

राज्य का विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार , गाँव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होते है।

अतः कथन 2 गलत है।

Q. 123) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. यदि कोई व्यक्ति पच्चीस वर्ष से कम आयु का है तो उसे पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
2. संविधान के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 123) Solution (d)

21 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।

अतः कथन 1 गलत है।

किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत , राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है।

अतः कथन 2 गलत है।

Q. 124) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक नगरपालिका (जब तक कि किसी विधि के अंतर्गत समय से पूर्व भंग न हो जाए) अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक कार्यरत रहेगी।
2. किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित किसी नगरपालिक का कार्यकाल प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक जारी रहेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 124) Solution (b)

प्रत्येक नगरपालिका (जब तक कि किसी विधि के अंतर्गत समय से पूर्व भंग न हो जाए) अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच साल तक कार्यरत रहेगी।

अतः कथन 1 सही है।

किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित कोई नगरपालिक, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी।

अतः कथन 2 गलत है।

Q. 125) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 243 **X** के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा।
2. सहकारी समिति के बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 125) Solution (d)

अनुच्छेद 243-**I** के तहत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा।

अतः कथन 1 गलत है।

बोर्ड का चुनाव, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर तुरंत पद ग्रहण करें।

अतःकथन 2 गलत है।

Q. 126) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अशोक मेहता समिति द्वारा त्रि -स्तरीय पंचायत-राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी
2. आंध्र प्रदेश पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 126) Solution (d)

त्रि-स्तरीय पंचायत-राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अतः कथन 1 गलत है।

1959 में राजस्थान, नागौर जिले में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने 1959 में इस प्रणाली को अपनाया।

अतः कथन 2 गलत है।

Q. 127) भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. स्थानीय निकायों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

2. भारतीय संविधान के अनुसार, संघीय व्यवस्था में स्थानीय सरकार एक स्वतंत्र स्तरीय निकाय नहीं है
3. पंचायतों को सहायता अनुदान, भारत के समेकित कोष से दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 127) Solution (a)

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं

अतः कथन 1 सही है।

स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तरीय निकाय है

अतः कथन 2 गलत है

पंचायतों को सहायता अनुदान, राज्य के समेकित कोष (भारत नहीं) से दी जाती है।

अतः कथन 3 गलत है।

Q. 128) भारत में पंचायत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधान पांचवें अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।
2. PESA को संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 128) Solution (a)

पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग IX पांचवें अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है, जो इस तरह के अपवादों और संशोधनों के अधीन हो सकते हैं।

अतः कथन 1 सही है

PESA पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों (पांचवीं अनुसूची) के संबंध में है, न कि जनजातीय क्षेत्रों (छठी अनुसूची) में।

अतः कथन 2 गलत है

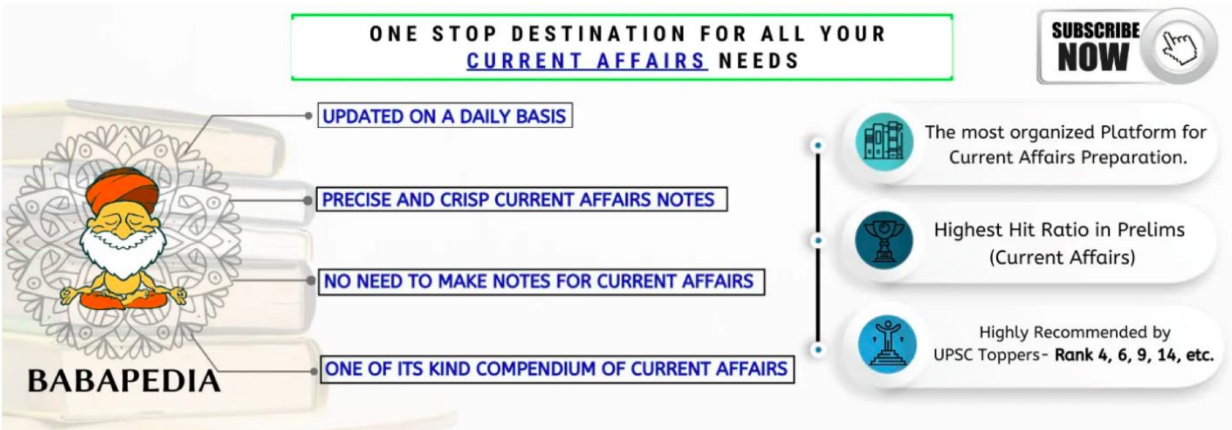

Q. 129) निम्नलिखित में से कौन 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है?

1. पंचायतों द्वारा लगान, वसूली और उचित कर, टोल और शुल्क अधिकृत करना
2. सभी स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 129) Solution (d)

स्वैच्छिक प्रावधान

किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।

पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, यानी उन्हें लगान, वसूली और उचित कर, टोल और शुल्क जमा करना।

अनिवार्य प्रावधान

तीनों स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।

अतः कथन 1 और 2 अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं

Q.130) भारत में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा / से कथन असत्य हैं / हैं?

1. अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से मनोनीत निकाय है।
2. मेयर एक नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है
3. एक नगर निगम में दो प्राधिकरण होते हैं, अर्थात् स्थायी समितियाँ और आयुक्त।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 2 और 3
b) 1 केवल
c) केवल 1 और 2
d) केवल 3

Q. 130) Solution (a)

अधिसूचित क्षेत्र समिति पूरी तरह से मनोनीत निकाय है

अतः कथन 1 सही है

नगरपालिका आयुक्त परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, वह निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

अतः कथन 2 गलत है

एक नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं, अर्थात् परिषद, स्थायी समितियाँ और आयुक्त।

अतः कथन 3 गलत है

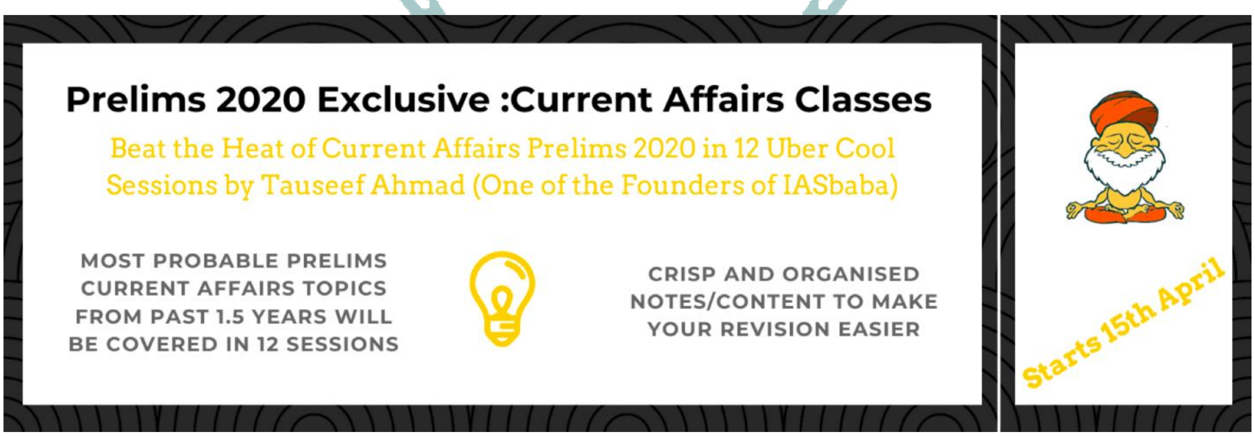

Q. 131) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता के लिए (चुनाव आयोग से परामर्श के बाद) प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।

2. संविधान के अनुसार, क्षेत्रीय आयुक्तों के सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 131) Solution (d)

प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त कर सकता हैं, अगर उसे लगता है की चुनाव आयोग की सहायता के साथ-साथ आयोग में दिए गए कार्यों के संचालन के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की आवश्यकता हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति के नियम के अनुसार निर्धारित होंगी।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 132) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य का विधानमंडल समय-समय पर (जहां तक संसद द्वारा निमित्त उपबंध नहीं है) विधि द्वारा, उस राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन में या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने या तो विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध नियम बना सकती है।
2. प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक संसद के किसी भी सदन के चुनाव के लिए तथा एक राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए दो मतदाता सूची होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 132) Solution (a)

किसी राज्य का विधानमंडल समय-समय पर (जहां तक संसद द्वारा निमित्त उपबंध नहीं है) विधि द्वारा, उस राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन में या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने या तो विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी मामलों के

संबंध में नियम बना सकती है । सदन या राज्य के विधानमंडल के चुनाव जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और ऐसे सदन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में निर्वाचन के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 133) अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है।
2. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 133) Solution (a)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 134) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी सुनुश्चित करना और सलाह देना आयोग का कर्तव्य होगा।
2. आयोग को संविधान (92 संशोधन) अधिनियम के माध्यम से एक संवैधानिक निकाय बन गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 134) Solution (c)

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी सुनुश्चित करना और सलाह देना एवं संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना आयोग का कर्तव्य होगा।

अतः कथन 1 सही है।

आयोग को संविधान (102 संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से एक संवैधानिक निकाय बन गया।

अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q. 135) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्यों के निष्पादन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा।
2. GST परिषद का प्रत्येक निर्णय कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 135) Solution (d)

विधान के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल अपने कार्यों के प्रक्रिया का निर्धारण स्वयंम करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम तीन-चौथाई मतों के बहुमत से एक बैठक में लिया जाएगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 136) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
2. राज्यपाल आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ राज्य विधायिका के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 136) Solution (c)

राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्यपाल आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ राज्य विधायिका के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 137) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्द्ध संघीय निकाय का रूप में प्रदान करता है।
2. संविधान में भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग की परिकल्पना की गई है।
3. पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्षत श्री. एन.के.सिंह ने 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 137) Solution (a)

अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्ध-न्यायिक निकाय का रूप प्रदान करता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारी के विभाजन से है। भारतीय संविधान राजकोषीय संघवाद के चक्र को संतुलित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना करता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्षत श्री. एन.के.सिंह ने 1 अप्रैल**,** 2020 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 138) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण करता है।
2. UPSC के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है
3. किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय UPSC से परामर्श नहीं किया जाता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 138) Solution (d)

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की संरचना निर्धारित करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

UPSC के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय UPSC से सलाह नहीं ली जाती है

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 139) निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबधित है / हैं:

1. SC के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी और उनके काम का मूल्यांकन करना।

2. संविधान के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
3. आयोग संसद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 2 और 3
b) केवल 1
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3

Q. 139) Solution (c)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी और उनके मूल्यांकन का काम करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

इसलिए कथन 2 सही है।

आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति (संसद नहीं) को प्रस्तुत करता है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q.140) भारत में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
5. राज्य के महाधिवक्ता

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 2 और 3
b) केवल 1, 4 और 5
c) केवल 2, 3 और 4
d) केवल 2, 3, 4 और 5

Q. 140) Solution (a)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी), भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, राज्य के एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक निकाय है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007) सांविधिक निकाय हैं।

Q. 141) राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
2. अधिनियम के तहत, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए) के साथ परामर्श करके सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 141) Solution (b)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

इसलिए कथन 1 सही है।

केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए, विशेष न्यायालय के रूप में सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को नामित करेगी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 142) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होंगे

2. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 142) Solution (a)

केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होंगे।

इसलिए कथन 1 सही है।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधान मंत्री, कैबिनेट रैंक का एक केन्द्रीय मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 143) केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी।
2. मुख्य सूचना आयुक्त की योग्यता उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश के सामान होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 143) Solution (d)

केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को सार्वजनिक जीवन में कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 144) नीति आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें विधानसभाएँ है, नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) में प्रतिनिधित्व करती है।
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (NILERD) एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो नीति आयोग से सम्बंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 144) Solution (a)

शासी परिषद: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधानसभाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों (यानी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर) और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

अतः कथन 1 सही नही है।

भारत सरकार ने 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (NILERD) की स्थापना की। यह योजना मंत्रालय नीति आयोग से जुड़ी एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 145) भारत के महा-अधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महा-अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।
2. संविधान के अनुसार, महा-अधिवक्ता को उनके कार्यालय से उस तरीके से महाभियोग लगा कर हटाया जाएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 145) Solution (d)

राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो भारत के लिए महा-अधिवक्ता होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।

इसलिए कथन 1 गलत है।

महा-अधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेगा, और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 146) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. NHRC के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जांच करने, अभियोजन की सिफारिश करने और मुआवजे देने की व्यापक शक्ति है।
2. NHRC कोई भी कठोर उपाय कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो इसके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 146) Solution (b)

NHRC के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जांच करने, अभियोजन की सिफारिश करने और मुआवजे देने की व्यापक शक्ति है।

इसलिए कथन 1 सही है।

आयोग के कार्य की प्रकृति मुख्य रूप से सिफारिशी हैं। मानवाधिकार आयोग को उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, न ही पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित कोई अन्य राहत देने के लिए।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 147) निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थापना के उद्देश्य हैं / हैं:

1. पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए।
2. व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 147) Solution (c)

पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए ।

इसलिए कथन 1 सही है।

व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 148) लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था?

a) महाराष्ट्र
b) कर्नाटक
c) उत्तर प्रदेश
d) केरल

Q. 148) Solution (a)

1971 में 'लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम' के माध्यम से महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की प्रणाली स्थापित की, और इसके साथ लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की संस्थाएँ 25 अक्टूबर, 1972 को अस्तित्व में आईं।

Q. 149) निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अंतर्गत आते है?

1. सशस्त्र बल
2. भारत के प्रधान मंत्री
3. समूह 'ए' या समूह 'बी' अधिकारी
4. समूह 'सी' या समूह 'डी' के अधिकारी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) 1, 2 और 3

b) 2, 3 और 4

c) 3 और 4

d) 1, 2, 3 और 4

Q. 149) Solution (b)

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, जिसे आमतौर पर लोकपाल अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में भारतीय संसद का भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम है, जो "कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और उन्हें सम्बंधित मामलों के लिए लोकपाल संस्था की स्थापना प्रयास करता है"।

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:

- भारत के प्रधान मंत्री
- संघ के सभी मंत्री
- संसद के सदस्य
- समूह 'ए' या समूह 'बी' अधिकारी
- समूह 'सी' या समूह 'डी' के अधिकारी

Q.150) केंद्रीय सतर्कता आयोग (**CVC**) के संदर्भ में**,** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना संथानम समिति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा की गई थी।
2. मूल रूप से CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और न ही एक वैधानिक निकाय लेकिन 2003 में संसद ने CVC पर वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया।
3. इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ हैं और इसक चरित्र न्यायिक होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.150) Solution (d)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की संथानम समिति द्वारा की गई थी।

इसलिए कथन 1 सही है।

मूल रूप से CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और न ही एक वैधानिक निकाय लेकिन 2003 में संसद ने CVC पर वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया।

इसलिए कथन 2 सही है।

इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसक चरित्र न्यायिक होता है

इसलिए कथन 3 सही है।

Q. 151) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. NDMA के अध्यक्ष की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
2. NDMA अध्यक्ष के लिए NDMA के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत सदस्यों में से एक को नामित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 151) Solution (a)

भारत के प्रधानमंत्री NDMA के पदेन अध्यक्ष हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

NDMA अध्यक्ष के लिए NDMA के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत सदस्यों में से एक को नामित करती है। उप-अध्यक्ष को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 152) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय का उल्लेख है।
2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भारत में और उसके बाहर लोक सेवकों पर लागू होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 152) Solution (c)

लोकपाल और लोकायुक्त, 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय है।

इसलिए कथन 1 सही है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भारत में और उसके बाहर लोक सेवकों पर लागू होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 153) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकपाल सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के सदस्य पचास प्रतिशत से कम नहीं होंगे।
2. लोकपाल का सदस्य किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 153) Solution (b)

लोकपाल के सदस्यों में न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।

इसलिए कथन 1 गलत है।

लोकपाल का सदस्य किसी भी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 154) नीति आयोग (NITI Aayog) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
2. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 154) Solution (d)

नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

इसलिए कथन 1 सही है।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग के कार्यों में से एक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 155) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भाग XIV-A (न्यायाधिकरण) को 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है।
2. अनुच्छेद 323 B केवल सार्वजानिक सेवा मामलों के न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 155) Solution (d)

भाग XIV-A (ट्रिब्यूनल) भारत के संविधान में 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 323 A केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 156) राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
2. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता तथा हटाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 156) Solution (a)

राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है**,** लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 157) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है।
2. सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 157) Solution (c)

सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

CBI की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 158) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनआईए को नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
2. एनआईए कुछ निश्चित कानूनों के तहत अपराधों से डील करता है, जिनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 भी शामिल है

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 158) Solution (c)

NIA को संसद के एक अधिनियम द्वारा नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बनाया गया था।

इसलिए कथन 1 सही है।

एनआईए कुछ निश्चित कानूनों के तहत अपराधों से डील करता है, जिनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 भी शामिल है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 159) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (SAT) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) स्थापित करने का अधिकार देता है।
2. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (SAT) राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 159) Solution (d)

1985 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) स्थापित करने का अधिकार है।

इसलिए कथन 1 सही है।

SAT राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.160) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) किन लोक सेवकों की भर्ती और सेवा मामलों के संबंध में अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है:

1. रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी
2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी
3. अखिल भारतीय सेवाएँ
4. संसद का सचिवीय कर्मचारी
5. राज्य सरकार के कर्मचारी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1, 2 और 3
c) केवल 2, 4 और 5
d) केवल 3

Q.160) Solution (a)

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) लोक सेवकों की भर्ती और सेवा मामलों के संबंध में अपने मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक विस्तारित है। हालांकि, रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के सेवक और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं।

Q. 161) मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस पद को पाँच वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा, जिस तिथि से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा।
2. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 161) Solution (a)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस पद को तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाया जाएगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 162) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुख्य सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा।
2. मुख्य आयुक्त के वेतन और भत्ते देय मुख्य सूचना आयुक्त **के** समान ही होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 162) Solution (d)

मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद को तब तक धारण करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

इसलिए कथन 1 गलत है।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए देय वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 163) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित है।
2. यह अधिनियम तब लागू नहीं होता है, जब एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को लिखित रूप में तालाक दिया गया हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 163) Solution (a)

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

यदि मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों में या तो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से तलाक़ की घोषणा की जाती है, तो शून्य होगा और अवैध भी होगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 164) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम के रूप में यह कोई अन्य विकल्प प्रदान नहीं करता है, एक नाबालिग बच्चे को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करने के लिए 18 साल के होने तक का इंतजार करना पड़ता है।
2. अधिनियम में उल्लिखित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 164) Solution (c)

एक नाबालिग बच्चे के मामले में, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया जाएगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अधिनियम में उल्लिखित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 165) आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आग्नेयास्त्रों (firearms) और गोला-बारूद (ammunition) के अधिग्रहण और अधिकार के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की समय अवधि कम करके पांच साल से तीन साल तक करता है।
2. कोई भी यदि बल का प्रयोग करके, पुलिस या सशस्त्र बलों से आग्नेयास्त्र छीन लेता है, तो इस कृत्य के लिए कारावास के साथ दंड का भी प्रावधान होगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 165) Solution (b)

यह आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस के नवीकरण की समय अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर देता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

कोई भी अगर बल का प्रयोग करके, पुलिस या सशस्त्र बलों से आग्नेयास्त्र छीन लेता है ,तो इस कृत्य के लिए कारावास के साथ दंड का भी प्रावधान होगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा, आगे इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 166) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हालांकि संविधान ने पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली को त्याग दिया है, लेकिन यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रदान करता है।
2. यद्यपि संविधान ने राज्यसभा के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, लेकिन उसने लोकसभा के मामले में समान प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 166) Solution (b)

संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को त्याग दिया है, हालांकि यह जनसंख्या अनुपात के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

हालांकि संविधान ने राज्यसभा के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, लेकिन उसने लोकसभा के मामले में समान प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी है। इसके बजाय, इसने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 167) भारतीय संविधान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है।
2. संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है लेकिन निवास स्थान पर नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 167) Solution (c)

किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है लेकिन निवास स्थान पर नहीं।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 168) मंत्रिपरिषद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के निर्णयों को माने तथा उसका संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इसका समर्थन करे।
2. राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 168) Solution (c)

.

प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों को माने तथा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इसका समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है और वह इसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 169) भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाने / घटाने की शक्ति होती है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा क्षेत्रीय आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 169) Solution (c)

चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की कितनी संख्या शामिल होगी, यदि कोई हो, तो राष्ट्रपति उसे समय-समय पर तय कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा क्षेत्रीय आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.170) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती हैं।
2. राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति या जनजाति का कोई भी समावेशन या बहिष्करण (exclusion) केवल संसद द्वारा किया जा सकता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.170) Solution (c)

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति या जनजाति का कोई भी समावेश या बहिष्करण केवल संसद द्वारा किया जा सकता है

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 171) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संशोधन केंद्र सरकार को कुछ असाधारण परिस्थितियों में आलू, प्याज की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है।
2. संशोधन केंद्र सरकार को खराब न होने योग्य (non-perishable) कृषि खाद्य पदार्थों पर स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार देता है, केवल जब उनके खुदरा मूल्य में सौ प्रतिशत वृद्धि हो जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 171) Solution (b)

संशोधन केंद्र सरकार को कुछ असाधारण परिस्थितियों में आलू, प्याज की आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संशोधन केंद्र सरकार को खराब न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों पर स्टॉक लिमिट लगाने का अधिकार देता है, केवल जब उनके खुदरा मूल्य में पचास प्रतिशत की वृद्धि होती है। केंद्र सरकार बागवानी उत्पादों पर स्टॉक सीमा तभी लगा सकती है, जब इसके खुदरा मूल्य में सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 172) द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अध्यादेश भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 के तहत गठित केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद को निलंबित करता है।
2. इस अध्यादेश के तहत केंद्रीय परिषद के समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 172) Solution (c)

अध्यादेश भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 के तहत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद को निलंबित करता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

इस अध्यादेश के तहत केंद्रीय परिषद के समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 173) मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 के तहत प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को भुगतान किए गए समतलीकरण भत्ते (sumptuary allowance) में 30 प्रतिशत की कटौती होगी।
2. भत्ते में कटौती 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी और एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 173) Solution (d)

प्रत्येक मंत्री को वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 के तहत दिए गए समतलीकरण भत्ते को 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भत्ते में कटौती 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होगी और एक वर्ष की अवधि के लिए होगी**,** इसका प्रयोग कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पूरा करने के लिए है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

Q. 174) महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अध्यादेश 'स्वास्थ्य सेवा कर्मियों' (Healthcare service personnel) शब्द को परिभाषित करता है।
2. स्वास्थ्य सेवा कर्मियों (अध्यादेश में उल्लिखित) के खिलाफ किया गया दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 174) Solution (d)

अध्यादेश 'हेल्थकेयर सेवा कर्मियों' शब्द को परिभाषित करता है।

अध्यादेश स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसे महामारी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते समय महामारी के संक्रमण का खतरा होता है (जैसा कि वह प्रभावित रोगियों के संपर्क में आ सकता है)।

इसलिए कथन 1 सही है।

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों (अध्यादेश में उल्लिखित) के खिलाफ किया गया दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 175) नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 में बच्चों के अधिकार के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 6 वीं कक्षा तक हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में कोई नियमित परीक्षा नहीं होगी।
2. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 175) Solution (b)

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा में एक नियमित परीक्षा होगी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 176) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है तथा एक कार्यकारी शक्ति (executive power) है

2. राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड के निलंबन (suspension), परिहार (Remission) और लघुकरण (Commutation) के संबंध में समवर्ती शक्ति प्राप्त है

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 176) Solution (c)

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है और एक कार्यकारी शक्ति (executive power) है

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड के निलंबन (suspension), परिहार (Remission) और लघुकरण (Commutation) के संबंध में समवर्ती शक्ति प्राप्त है

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 177) निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. इसे किसी भी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है।
3. यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय से इस्तीफा दे देना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3

Q. 177) Solution (c)

इसे किसी भी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध पेश किया जा सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है।

इसलिए कथन 2 सही है।

यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

Q. 178) निजी विधेयक/ गैर-सरकारी विधेयक (Private Bill) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. यह संसद के किसी भी सदस्य द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, के द्वारा पेश किया जाता है।
2. सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 178) Solution (c)

यह संसद के किसी भी सदस्य द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, के द्वारा पेश किया जाता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q. 179) राज्य विधानमंडल में एक साधारण विधेयक के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विधान परिषद, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या टाल सकती है।
2. जो विधेयक, विधान परिषद में पेश किया गया है और विधानसभा को भेजा गया हो, उसे अगर विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बिल समाप्त हो जाता है और शून्य हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 179) Solution (c)

परिषद, अधिकतम चार महीने की अवधि के लिए बिल को रोक सकती है या टाल सकती है - पहली बार में तीन महीने और दूसरे बार में एक महीने।

इसलिए कथन 1 सही है।

विधेयक, जो परिषद में उत्पन्न हुआ है और विधानसभा को भेजा गया था, अगर विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बिल समाप्त हो जाता है और मृत हो जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

Q.180) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. दसवीं अनुसूची को 91 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है।
2. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न राज्यपाल द्वारा तय किया जाएगा और निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.180) Solution (d)

दसवीं अनुसूची को 52 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने का प्रश्न विधान परिषद के मामले में सभापति और विधान सभा के मामले में स्पीकर/ अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस संबंध में अध्यक्ष / अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

इसलिए कथन 2 गलत है।